

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

पहलगाम आतंकी हमला: चुनौतियाँ और
आगे की राह

www.nextias.com

पहलगाम आतंकी हमला: चुनौतियाँ और आगे की राह

संदर्भ

- पहलगाम में हाल में हुआ आतंकवादी हमला भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि इससे आर्थिक पुनरुद्धार और सामान्यीकरण के प्रयासों पर खतरा मंडरा रहा है, तथा खुफिया एवं सुरक्षा उपायों में लंबे समय से चली आ रही चूक भी प्रकट होती है।

आतंकवाद के बारे में

- इसे व्यापक रूप से राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध हिंसा और धमकी के गैरकानूनी उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
 - यह एक वैश्विक चुनौती है जो शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों को कमजोर करती है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे सामान्यतः नागरिकों या गैर-लड़ाकों को मौत या गंभीर हानि पहुँचाने की इच्छा से किए गए कार्यों के रूप में समझा जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या को डराना या सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कार्रवाई करने या कार्रवाई करने से मना करने के लिए मजबूर करना है।
- भारत के संदर्भ में, आतंकवाद में प्रायः सीमा पार की गतिविधियाँ, उग्रवाद और कट्टरपंथी हमले शामिल होते हैं।
 - गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967, एक आतंकवादी कृत्य को ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुँचाता है या हिंसा का उपयोग करके या आवश्यक सेवाओं को बाधित करके लोगों में आतंक पैदा करता है।

भारत में आतंकवाद के प्रकार

- **सीमा पार आतंकवाद:** लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे समूह पाकिस्तान से कार्य करना जारी रखते हैं, जो जम्मू-कश्मीर में नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं।
 - इसमें मुंबई हमले (2008), पठानकोट एयरबेस हमला (2016) और पुलवामा बम विस्फोट (2019) शामिल हैं।
- **पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद:** मणिपुर, असम एवं नागालैंड जैसे राज्य जातीय शिकायतों और अलगाववादी माँगों के कारण उग्रवाद का सामना कर रहे हैं।
 - छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में 'रेड कॉरिडोर' में माओवादी (नक्सली) खतरा लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है।
- **साइबर आतंकवाद और वित्तपोषण:** आतंकवादी क्रिप्टोकॉर्सेसी और डार्कनेट का उपयोग करके प्रचार, भर्ती और धन उगाहने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से लाभ उठा रहे हैं।
- **शहरी कट्टरपंथ और लोन-वुल्फ हमले:** लोन-वुल्फ हमलों और ऑनलाइन कट्टरपंथ के बढ़ने से भारत की सुरक्षा चुनौतियों में नए आयाम जुड़ गए हैं।
 - द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे समूह हाइब्रिड आतंकवाद की रणनीति का उपयोग करते हैं, लक्षित हमलों के लिए कट्टरपंथी स्थानीय लोगों को नियुक्त करते हैं।

आतंकवाद विरोधी प्रयासों में चुनौतियाँ

- **खुफिया और सुरक्षा खामियाँ:** निगरानी में प्रगति के बावजूद, खुफिया जानकारी साझा करने में चूक के कारण पहलगाम की घटना सहित बड़े हमले हुए हैं।
 - मानव खुफिया नेटवर्क और साइबर निगरानी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

- **सुरक्षा और खुफिया चुनौती:** यह हमला पिछले साल बार-बार आतंकवादी हमलों के बावजूद जम्मू-कश्मीर में खुफिया और सुरक्षा तंत्र में लंबे समय से चली आ रही अपर्याप्तता को भी प्रकट करता है।
- **भौगोलिक विस्तार:** आतंकवादी गतिविधियाँ, जो कभी कश्मीर घाटी तक सीमित थीं, अब जम्मू तक फैल गई हैं, जहाँ 2021 और 2024 के बीच 30 से अधिक हमले हुए हैं, जिनमें से कई में नागरिक हताहत हुए हैं।
- **घरेलू उग्रवाद:** सोशल मीडिया और धार्मिक प्रचार के माध्यम से कट्टरपंथ घरेलू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।
 - इंडियन मुजाहिदीन (IM) और कुछ ISIS-प्रेरित मॉड्यूल जैसे समूह हाल के वर्षों में उभरे हैं।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक निकटता ने विरोधियों से शत्रुता बढ़ा दी है।
 - 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया है।
- **सार्वजनिक भावना और सांप्रदायिक सद्भाव:** आतंकवादी हमले प्रायः सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे सरकार के लिए गलत सूचना और सामाजिक अशांति को रोकना अनिवार्य हो जाता है।

आतंकवाद विरोधी प्रयास

- **कानूनी ढांचा:**
 - गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम एजेंसियों को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में लेबल करने का अधिकार देता है।
 - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम ने अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र के साथ एक केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी बनाई।
- **संस्थागत तंत्र:**
 - NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग खुफिया जानकारी एकत्र करने और लागू करने में महत्वपूर्ण हैं।
 - मल्टी-एजेंसी सेंटर अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करता है।
- **तकनीकी एकीकरण:**
 - चेहरे की पहचान, ड्रोन निगरानी और AI-सक्षम खतरे के विश्लेषण की तैनाती सीमा और शहरी निगरानी को बढ़ाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
 - भारत खुफिया जानकारी साझा करने और कट्टरपंथ विरोधी प्रयासों पर अमेरिका, इजरायल और अन्य देशों के साथ सहयोग करता है। यह वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढाँचे का भी हिस्सा है जैसे:
 - वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
 - संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति
- **कट्टरपंथ-विरोधी पहल:** राज्य पुलिस और खुफिया शाखाएँ, विशेष रूप से केरल और महाराष्ट्र में, कमजोर युवाओं को लक्षित करके सामुदायिक आउटरीच और कट्टरपंथ-विरोधी कार्यक्रम चलाती हैं।

हाल की सरकारी पहल

- **NATGRID:** वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस।
- **सुरक्षित शहर परियोजनाएँ:** स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी निगरानी।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC)

आगे की राह: भारत की आतंकवाद निरोधी रणनीति को मजबूत करना

- **उन्नत सुरक्षा अवसंरचना:** उन्नत निगरानी तकनीकों को तैनात करना, जिसमें AI-संचालित खतरे का पता लगाना शामिल है।
 - ♦ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष बलों के संचालन का विस्तार करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ आतंकवाद विरोधी साझेदारी को मजबूत करना।
 - ♦ वैश्विक आतंकी नेटवर्क पर नज़र रखने के लिए संयुक्त खुफिया-साझाकरण पहल।
- **सामान्य स्थिति पुनर्स्थापित करना:** तत्काल कदम सुरक्षा को बढ़ावा देने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित होने चाहिए।
 - ♦ विश्वास-निर्माण उपाय हमले से उत्पन्न हुए भय का मुकाबला करने में सहायता कर सकते हैं।
- **सामुदायिक जुड़ाव और डी-रेडिकलाइजेशन:** कट्टरपंथी व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को लागू करना।
 - ♦ चरमपंथी आख्यानो का मुकाबला करने के लिए अंतर-धार्मिक संवादों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

- पहलगाम हमला न केवल निर्दोष लोगों की जान पर हमला है, बल्कि जम्मू-कश्मीर के पुनरुत्थान के मूल ढाँचे पर भी हमला है।
- सरकार को तत्काल सुरक्षा चूक को दूर करना चाहिए, साथ ही उसे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक उपाय भी करने चाहिए।
- विश्वास बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकवाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति को पटरी से न उतार सके, एक सुनियोजित और निर्णायक प्रतिक्रिया आवश्यक है।

Source: BS

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा, भू-राजनीतिक दबाव और सांप्रदायिक सद्भाव को संतुलित करते हुए, आतंकवाद की उभरती प्रकृति से निपटने के लिए भारत को क्या उपाय अपनाने चाहिए?

■■■■